(ख) यदि हां, तो उससे कितना सोना मिलने की आशा है ; और

(ग) खुदाई का काम किस तारीख से आरम्भ किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश मे मुख्य ज्ञात सोना वाले क्षेत्र अनन्तपुर जिले मे रामगिरी सोना क्षेत्र है जहा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा विस्तृत अन्वेषण किए गए है जिन्होने यह उपदर्शित किया है कि इस निक्षेप के खान के रूप म विकास किए जा सकने की सम्भावना है। आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार के परामर्श के साथ निक्षेप के वाणिज्यिक मात्रा मे समुपयोजन के प्रश्न का परीक्षण किया जा रहा है।

उस राज्य मे किसी अन्य नए सोना निक्षेप का पता नही चला है। तथापि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा खान और भूविज्ञान विभाग, आन्ध्र प्रदेश द्वारा महबूब नगर जिले के नारायनपेट क्षेत्र मे मार्च, 1970 मे विस्तृत अन्वेषण किए गए परन्तु इन अन्वेषणो द्वारा इस क्षेत्र मे सोना प्राप्ति की कोई सम्भावना उद्घाटित नही हुई।

Paid Holiday on Polling Day

474. SHRI M. RAM GOPAL REDDY . Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION (SHRAM AUR PUNARVAS MANTRI) be pleased to state :

(a) whether the polling day in the country is not a paid holiday for workers ; and

(b) if so, whether Government would consider amending the law to make polling day a paid holiday for workmen ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRAM AUR PUNARVAS MANTRI) (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) No, Sir. Government of India however issued instructions to the effect that in respect of Central Government Offices and also in respect of Industrial Establishments under the Central Government a paid holiday may be granted on the polling day, if it does not fall on a Sunday or a paid holiday, provided the State Government concerned have declared that day as a local holiday in the area.

(b) There is no Central enactment relating to Holidays to workmen in general.

Return of Defective Tractors imported from East Germany

475 SHRI BISHWANATH JHUNJHUNWALA :
SHRI T. S LAKSHMANAN :
SHRI C CHITTIBABU :

Will the Minister of AGRICULTURE (KRISHI MANTRI) be pleased to state :

(a) whether Government have requested the East German Government to take back tractors supplied by them which later on were found to be defective ;

(b) whether the East German Government have acceded to the request ;

(c) if so, at whose cost and expense the tractors will be sent back ; and

(d) whether the East German Government will take back only the unsold tractors or all the tractors which have been sold by them and which, after sale, developed trouble ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA MEN RAJYA MANTRI) (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) to (d). The GDR Suppliers have agreed to take back modified RS-09 tractors. A copy of the Protocol signed between the State Trading Corporation and the GDR Suppliers on the 21st February, 1971 is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-211/71]. Return of these tractors is to be arranged by the concerned State Agro-Industries Corporations according to the

terms specified in the Protocol. The formula for sharing the loss as between the farmers and the Agro-Industries Corporations is under active consideration of the latter.

देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए अविलम्बनीय कार्यक्रम

476. **श्री रामावतार शास्त्री**
श्री बी० के० दासचौधरी :
श्री डी० के० पडा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए नियत 50 करोड़ रुपयों का उपयोग करने के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को भी इस बारे में अपने विचार व्यक्त करने को कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त विचारों का ब्योरा क्या है तथा उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). वर्ष 1971-72 में 50 करोड़ रु० के परिव्यय की ग्राम रोजगार की त्वरित योजना बनाई गई है। यह योजना केन्द्रीय सरकार की शत प्रतिशत वित्तीय सहायता से राज्य सरकारों, केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। अतिरिक्त रोजगार श्रम-प्रधान तथा स्थायी स्वरूप की परिसम्पत्तियां तैयार करने वाली विभिन्न किस्मों की ग्राम परियोजनाओं के जाल के माध्यम से पैदा करने का इरादा है। प्रत्येक जिले मे कम से कम 1,000 व्यक्तियों को वर्ष भर में दस महीनों के लिए 100 रु० प्रतिमास तक मजदूरी पर रोजगार दिया जाना है। मजदूरी की लागत के एक चौथाई के बराबर की राशि सामग्री तथा उपकरणो के लिए उपलब्ध होगी। परिव्यय की राशि 12.50 लाख रु० प्रति जिला प्रति वर्ष होगी।

(ग) और (घ). यह योजना राज्यो को भेजी गई थी। बारह राज्य सरकारे और सात केन्द्र शासित प्रशासन प्रस्ताव भेज चुके है, जिनमें इस योजना के अन्तर्गत आरम्भ की जाने वाली कुछ परियोजनाओ का ब्यौरा दिया गया है। आठ राज्यो और छ केन्द्र शासित क्षेत्रो के प्रस्तावो को कार्यान्वित करने के लिए मजूरी दे दी गई है। शेष राज्यो के प्रस्तावो की जांच की जा रही है।

Import of Suitable Tractors in Replacement of Defective RS-09 Tractors Imported from G.D.R.

478. SHRI R. S. PANDEY : Will the Minister of AGRICULTURE (KRISHI MANTRI) be pleased to state :

(a) whether all the tractors imported from East Germany which were found defective have since been returned to that country ;

(b) the arrangements made by the Government to import better tractors in replacement of defective RS-09 tractors for supply to farmers to whom they were meant to be supplied ;

(c) when the new tractors are likely to be procured and supplied to the farmers ; and

(d) the steps taken to ensure that the new tractors are found suitable to the requirements of the Indian farmers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA MEN RAJYA MANTRI) (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) A Protocol about the return of modified RS-09 tractors was signed between the State